नईदुनिया

तेल-तिलहन बाजार : सोयाबीन, बिनौला लुढ़के ; मूंगफली में चमक

पाम-पामोलीन में मामूली सुधार, पर लागत से नीचे बिकवाली जारी

नई दिल्ली

बीते सप्ताह खाद्य तेल बाजार में मिला-जुला रुख रहा। आयातकों द्वारा लागत से नीचे दाम पर बिकवाली और ब्रांडेड कंपनियों की कमजोर मांग के चलते सोयाबीन तेल-तिलहन व बिनौला तेल के दाम गिरे। इसके विपरीत, मजबूत मांग से मूंगफली तेल-तिलहन में सुधार दर्ज हुआ।

औद्योगिक मांग के कारण पाम-पामोलीन व सोयाबीन डीगम तेल में भी मामूली सुधार दिखा, जबकि सरसों तेल-तिलहन के दाम स्थिर बने रहे। बाजार सूत्रों के अनुसार, आयातकों को सोयाबीन डीगम तेल की लागत से 5-6 रुपये प्रति किलो कम (लगभग 119.50 रुपये प्रति किलो) पर बेचना पड़ा।

पाम-पामोलीन भी लागत से नीचे बिकवाली का शिकार हुआ। सोयाबीन के तेल रहित खल (डीओसी) के निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले 12.5 फीसदी की कमी तथा ब्रांडेड कंपनियों की घटती मांग से बिनौला तेल के दाम भी प्रभावित हुए। वहीं, मांग बढ़ने और आवक कमजोर रहने के कारण मूंगफली तेल-तिलहन में पर्याप्त सुधार आया।

किसानों की कम दाम पर फसल न बेचने की प्रवृत्ति और ऊंची खरीद पर पेराई मिलों के घाटे के चलते सरसों तेल-तिलहन पिछले सप्ताहांत के स्तर पर ही स्थिर रहे। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमश: 400-400 रुपये की गिरावट के साथ क्रमश: 6,300-6,350 रुपये और 6,150-6,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

इसी प्रकार, आयातकों की लागत से नीचे दाम पर बिकवाली की वजह से दिल्ली में सोयाबीन तेल 100 रुपये की गिरावट के साथ 15,500 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 100 रुपये की गिरावट के साथ 15,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दूसरी ओर, सोयाबीन डीगम तेल 100 रुपये सुधार के साथ 11,950 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।अच्छी मांग के कारण बीते सप्ताह मूंगफली तिलहन का दाम 250 रुपये के सुधार के साथ 7,600-8,175 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 500 रुपये के सुधार के साथ 17,500 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 75 रुपये के सुधार के साथ 2,755-3,055 रुपये प्रति टिन पर स्थिर बंद हुआ।

समीक्षाधीन सप्ताह में सीपीओ तेल का दाम 25 रुपये के सुधार के साथ 14,125 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलीन दिल्ली 25 रुपये के सुधार के साथ 16,025 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल 25 रुपये के सुधार के साथ 14,725 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।ब्रांडेड कंपनियों की कमजोर मांग के कारण बीते सप्ताह बिनौला तेल का दाम 300 रुपये की गिरावट के साथ 16,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

न्यूज ब्रीफ

आईटीसी का आशीर्वाद ब्रांड, पांच साल में 20,000 करोड़ का लक्ष्य , रेडी-टू-कुक, फ्रोजन फूड और सत्तू सहित नई श्रेणियों में भी होगा विस्तार

बेंगलुरु। आईटीसी अपने प्रमुख खाद्य ब्रांड आशीर्वाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में आशीर्वाद उत्पादों पर उपभोक्ता खर्च मौजूदा 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हो जाए। मई, 2002 में पूरी तरह गेहूं के आटा ब्रांड के रूप में शुरू हुआ आशीर्वाद अब देश के प्रमुख रसोई ब्रांडों में से एक बन गया है, जिसके पोर्टफोलियो में 200 से अधिक एसकेयू (स्टाक कीपिंग यूनिट्स) हैं। ब्रांड ने आटा के अलावा स्टेपल्स, मसाले, ताजे और फ्रोजन खाद्य पदार्थों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। मलिक के अनुसार, आटा श्रेणी में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। कंपनी मल्टीग्रेन, हाई-प्रोटीन, आर्गेनिक और मिलेट आधारित आटा जैसे प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो बेहतर गुणवत्ता, सुविधा और पोषण लाभ प्रदान करते हैं। आशीर्वाद अब बेसन, सेवई, रवा, सोया चंक्स, फ्रोजन नान और पराठे के साथ-साथ ताजी चटनी और सांभर जैसे उत्पादों के माध्यम से नए उपभोक्ता वर्ग और उपयोग के अवसर तलाश रहा है। रेडी-टू-कुक श्रेणी में भी कंपनी ने कदम बढ़ाया है, जिसमें तैयार चपातियां विशेष रूप से युवा परिवारों को ध्यान में रखकर पेश की गई हैं। ये चपातियां बिना किसी अतिरिक्त प्रिजर्वेटिव के 5-6 दिनों तक उपयोग की जा सकती हैं। आईटीसी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आशीर्वाद चना सत्तू भी पेश किया है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है।

आरबीआई का टाटा संस को लिस्टिंग का आदेश, छूट की अर्जी खारिज, बोर्ड में नेतृत्व की खींचतान के बीच फैसला, कुछ शेयरधारक पक्ष में तो कुछ विरोध में

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने खुद को अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) की श्रेणी से छूट देने की मांग की थी। इस फैसले से टाटा संस के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य हो गई है। आरबीआई ने 11 सितंबर को जारी एक पत्र में कहा कि टाटा संस की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। केंद्रीय बैंक ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) का दर्जा छोड़ने की मांग को भी नामंजूर कर दिया, जिससे कंपनी के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना अब जरूरी हो गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर न बने रहने की इच्छा जताई है, जिसकी वजह बोर्ड में चल रही असहमति बताई जा रही है।

यूपीआआई के बावजूद क्रेडिट कार्ड क्यों हैं खास जानें उनके नए फायदे!, छोटी से बड़ी हर खरीदारी के लिए लोगों की पहली पसंद बन चुका यूपीआई

नई दिल्ली। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने क्रांति ला दी है। छोटी से बड़ी हर खरीदारी के लिए लोगों की पहली पसंद बन चुका यूपीआई, अब डेबिट कार्ड के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड अपनी रणनीतियों में बदलाव लाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। देश में यूपीआई का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि किराना स्टोर से लेकर बड़े स्टोर तक, हर जगह क्यूआर कोड के जरिए भुगतान आम हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी सहजता और गति है। ग्राहक सिर्फ मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे बैंक खाते से पैसे भेज सकते हैं, जिससे कार्ड निकालने या पिन डालने की जरूरत खत्म हो गई है। इसी आसानी के चलते छोटे दुकानदार भी इसे तेजी से अपना रहे हैं।

फेड के बयान, महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर

पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद बाजार के लिए अहम रहेगा आगामी सप्ताह

मुंबई

घरेलू शेयर बाजारों के लिए आगामी सप्ताह बेहद अहम होने वाला है। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण देखी गई गिरावट के बाद, अब निवेशकों की निगाहें तीन प्रमुख वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतकों पर टिकी रहेंगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की महत्वपूर्ण बैठक, भारत के खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े, और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय चाल मिलकर इस सप्ताह बाजार की दिशा तय करेंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मुक्त बाजार समिति की बैठक 15 और 16 सितंबर को निर्धारित है।

इस बैठक में लिए जाने वाले नीतिगत फैसले और फेड चेयरमैन का बयान वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय शेयर बाजारों के लिए भी एक अहम दिशा निर्धारित करेगा। ब्याज दरों पर कोई भी संकेत या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फेड का दृष्टिकोण दुनियाभर के निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा।

फेड के किसी भी कठोर रुख से वैश्विक इक्विटी बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। घरेलू मोर्चे पर, भारत के खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई के आंकड़े इसी सप्ताह जारी होने वाले हैं। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि महंगाई उम्मीद से अधिक रहती है, तो यह बाजार की चिंताएं बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की अटकलें तेज होंगी। वहीं, नियंत्रण में रहने पर निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर निवेशकों की प्राथमिक चिंता का विषय बनी हुई हैं। पिछले सप्ताह इसमें आई भारी तेजी घरेलू बाजारों में गिरावट का एक प्रमुख कारण रही थी। इस सप्ताह भी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें न केवल कंपनियों की लागत बढ़ाती हैं, बल्कि महंगाई और रुपये पर भी दबाव डालती हैं, जिससे बाजार की धारणा प्रभावित होती है।

इंडियन बैंक जीवन बीमा एसेट मैनेजमेंट में उतरेगा, दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय और नए देशों में मौजूदगी की भी योजना

चेन्नई। सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन बैंक जीवन बीमा और संपत्ति प्रबंधन (म्यूचुअल फंड) कारोबार में उतरने की अपनी योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बैंक के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रस्तावित अनुषंगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के लिए जल्द ही निदेशक मंडल से मंजूरी ली जाएगी। अधिकारी ने पुष्टि की कि यह योजना पूरी तरह पटरी पर है। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, बैंक आवश्यक नियामकीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शुरू करेगा। कुमार ने इस पूरी कवायद में सही साझेदार की पहचान को सबसे महत्वपूर्ण बताया, जिससे तेजी से कारोबार का विस्तार और संपत्ति सृजन हो सके। उन्होंने अनुमान जताया कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक साल का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि अनुषंगी कंपनियां या संयुक्त उद्यम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जो संपत्ति सृजन के साथ-साथ ब्रांड को भी मजबूत करते हैं। इंडियन बैंक पहले से ही साधारण बीमा क्षेत्र में यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 28.52 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मौजूद है। वैश्विक विस्तार के मोर्चे पर, इंडियन बैंक दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में बसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय से मिलने वाले कारोबारी अवसरों का लाभ उठाना है। बैंक के बोर्ड ने दुबई कार्यालय को मंजूरी दे दी है और अब नियामकीय मंजूरियां ली जा रही हैं। इंडियन बैंक की वर्तमान में सिंगापुर और श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय शाखाएं हैं, जबकि बैंक मलेशिया और इंडोनेशिया में भी अपनी मौजूदगी स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

पेटेंट कार्यालय के लोगो के अनाधिकृत उपयोग पर नकेल, मंत्रालय की पूर्व-मंजूरी अनिवार्य

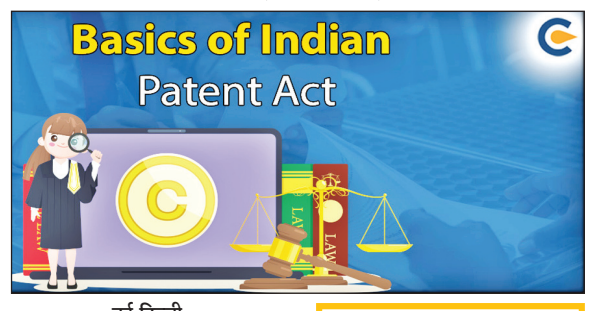

सरकारी पहचान का दुरुपयोग रोकने के लिए डीपीआईआईटी का सख्त कदम

नई दिल्ली

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) की आधिकारिक पहचान और लोगो के अनाधिकृत उपयोग पर अब सख्त रोक लगा दी गई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि आईपीओ के लोगो, प्रतीक चिह्न या उससे मिलते-जुलते डिजाइन का इस्तेमाल अब संबंधित मंत्रालय की पूर्व-मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, कारोबारी संस्था, डिजिटल मंच, ट्रेडमार्क या पेटेंट एजेंट अथवा कानूनी व्यवसायी किसी भी माध्यम - प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया, वेबसाइट या प्रायोजित आनलाइन विज्ञापन - में भारतीय पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक लोगो का उपयोग, अनुकूलन या प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं कर सकेंगे। पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) के संज्ञान में आया था कि कई व्यक्ति, एजेंसियां और आनलाइन कानूनी सेवा मंच अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया खातों और प्रचार सामग्री में भारतीय पेटेंट कार्यालय के लोगो का कथित रूप से अनाधिकृत इस्तेमाल कर रहे थे। डीपीआईआईटी ने चिंता व्यक्त की कि भारतीय पेटेंट कार्यालय का लोगो एक आधिकारिक सरकारी पहचान है और इसके अनधिकृत इस्तेमाल से आम लोगों, पेटेंट आवेदकों और अन्य हितधारकों के बीच सरकारी समर्थन या संबद्धता को लेकर गलत धारणा पैदा हो सकती है।

डीपीआईआईटी ने सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को अपनी वेबसाइट, प्रचार बैनर, विजिटिंग कार्ड और आनलाइन पोर्टलों से ऐसे लोगो या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते डिजाइन को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय के लोगो का अनाधिकृत इस्तेमाल, गलत प्रस्तुतीकरण या उसकी नकल प्रतीक और नाम (अनुचित इस्तेमाल को रोकने वाला) अधिनियम 1950, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कापीराइट अधिनियम 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है।

फार्मा पेटेंट जांच के लिए नए दिशानिर्देश, गुणवत्ता और एकरूपता पर जोर

नई दिल्ली। भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने औषधि क्षेत्र में पेटेंट आवेदनों की जांच प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतन करने का प्रस्ताव दिया है। जारी मसौदा दिशानिर्देशों में गुणवत्ता, निरंतरता और एकरूपता पर विशेष बल दिया गया है, साथ ही अदालतों के हालिया महत्वपूर्ण फैसलों को भी शामिल किया गया है। आईपीओ ने इस पहल का महत्व बताते हुए कहा कि भारत में फार्मास्युटिकल पेटेंट एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। जहां खराब पेटेंट समाज पर अनावश्यक बोझ बन सकते हैं, वहीं मजबूत और उचित पेटेंट नवोन्मेषण तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यालय ने बताया कि वह अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े तंत्र को लगातार बेहतर बना रहा है। दिशानिर्देशों का अद्यतन, विशेष रूप से उत्पाद पेटेंट से जुड़े कई मुद्दों पर अदालतों के स्पष्ट होते फैसलों को ध्यान में रखकर किया गया है।

एसएमएल लिमिटेड अगले 2-3 साल में हो सकती है सूचीबद्ध पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार में आने पर विचार

नई दिल्ली

कृषि आदान कंपनी एसएमएल लिमिटेड (पूर्व में सल्फर इंडिया लिमिटेड) अगले दो से तीन साल में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने पर विचार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य नई रासायनिक इकाइयों (एनसीई) के विकास के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना है। हालांकि, कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और कंपनी अगले एक-दो साल में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद कर रही है। मुंबई स्थित एसएमएल लिमिटेड उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से है जो नई और स्वामित्व वाली रासायनिक इकाइयों (एनसीई) पर काम कर रही है। ये सामान्य जेनेरिक उत्पादों से अलग कंपनी द्वारा विकसित किए गए नए अणु हैं। पिछले तीन वर्षों से कंपनी का यह एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र रहा है, हालांकि इसके विकास में प्रति एनसीई 7-8 करोड़ डालर का भारी निवेश होता है, जिसका खर्च कंपनी अब तक अपने आंतरिक शोध एवं विकास से उठा रही है।

कंपनी फिलहाल करीब 450-470 करोड़ रुपये की नकदी के साथ लगभग कर्ज-मुक्त स्थिति में है। प्रबंधन इस पूंजी का उपयोग भविष्य में अधिग्रहण, नियामकीय परिसंपत्तियों या एनसीई कार्यक्रम में रणनीतिक साझेदारी के लिए कर सकता है। एसएमएल अपने पारंपरिक सल्फर उर्वरक कारोबार से आगे बढ़कर फसल पोषण, फसल संरक्षण और जैविक उत्पादों पर भी ध्यान दे रही है, जिसमें फसल पोषण अगले तीन वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारोबार होने की उम्मीद है। कमजोर मानसून, अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क और भू-राजनीतिक तनाव के कारण परिवहन में बाधाओं को देखते हुए, एसएमएल ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना राजस्व लक्ष्य घटाकर 1,600 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पहले 1,800 करोड़ रुपये था। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष के 1,200-1,300 करोड़ रुपये के कारोबार से अधिक रहेगा। कंपनी ने उत्पादों की कीमतों में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की है। कंपनी का अंतरराष्ट्रीय कारोबार 80 से अधिक देशों में फैला है, जिससे पिछले वित्त वर्ष में 600-700 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इस वित्त वर्ष में इसके 700-800 करोड़ रुपये और अगले दो वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें निर्यात राजस्व में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी फसल संरक्षण उत्पादों (कीटनाशक और फफूंदनाशक) की है।

एशिया के बेस्ट वर्कप्लेस 2026 : भारत का दबदबा कायम, टाप-100 में 34 भारतीय कंपनियां

फ्लिपकार्ट, इंफोसिस समेत कई भारतीय कंपनियों का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली

दुनियाभर की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यस्थल सबसे बेहतर है, इसका पता लगाने के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की नई लिस्ट जारी की है। यह रैंकिंग कर्मचारियों की राय और उनके अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें भारत ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया है।

इस लिस्ट में शामिल टाप-100 बड़ी कंपनियों में 34 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, जो देश की मजबूत कार्य संस्कृति का प्रमाण है। ग्रेट प्लेस टू वर्क की यह प्रतिष्ठित लिस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के लगभग 89 लाख कर्मचारियों के अनुभवों को शामिल करते हुए तैयार की गई है। कर्मचारियों से कंपनी में भरोसे, नेतृत्व, काम के माहौल, नए विचारों को बढ़ावा, कंपनी के मूल्यों और उनके कुल अनुभव के बारे में पूछा गया था। इस अध्ययन में कंपनियों के आकार या कमाई की बजाय कर्मचारियों के वास्तविक अनुभव को ही मूल्यांकन का आधार बनाया गया है। बड़ी कंपनियों की श्रेणी में वैश्विक स्तर पर जिन 10 कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उनमें हिलटन, मैरियोट इंटरनेशनल, सिस्को, एब्बी, डीएचएल, इंटरकान्टिनेंटल होटल्स ग्रुप, माइक्रो टेक्नोलाजी, टीपी, एसेंचर और कैपेला का नाम शामिल है। इस पूरी रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है।

बड़ी कंपनियों की टाप-100 लिस्ट में 34 कंपनियां भारत की हैं। इनमें फ्लिपकार्ट ग्रुप, इंफोसिस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, रिलायंस रिटेल, बजाज फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर, उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक, जेनसर टेक्नोलाजीज, एक्सपीरियन, एडलवीज लाइफ और एचपी इंक जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा, छोटी और मध्यम कंपनियों की लिस्ट में एनआईए इंस्टीट्यूशंस, वहदम इंडिया, चैलेट होटल्स, सेरेंटिका रिन्यूबल इंडिया, किम्बल और एलएमएस (लार्ड महावीरा सर्विसेज इंडिया) सहित 6 भारतीय कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लिस्ट में शामिल लगभग 93 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी कंपनी को काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बताया। वहीं, ट्रस्ट इंडेक्स का औसत स्कोर 91 फीसदी रहा। कर्मचारियों ने खास तौर पर आफिस में सुरक्षा का अच्छा माहौल, नए कर्मचारियों का स्वागत और अपनापन, तथा सभी के साथ समान व्यवहार जैसे पहलुओं पर 95 फीसदी से अधिक सकारात्मक राय दी है, जो दर्शाता है कि कंपनियां कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही हैं।